Popular Front of India

+91 11 46526919
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
24 जून 2021

पॉपुलर फ्रंट ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते नफरती अपराधों और बदनाम करने के अभियान पर जताई चिंता

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में संगठन ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते नफरती अपराधों और बदनाम करने के अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

पिछले कुछ हफ्तों के अंदर विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की गई है। गाय के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग लगातार जारी है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में असम, राजस्थान और हरियाणा में कई लोगों की हत्या की गई है। नोएडा में एक हिंसक भीड़ ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मस्जिदों पर हमलों की ऐसी ही घटनाएं हरिद्वार और मथुरा में भी सामने आई हैं। जम्मू–कश्मीर के राजौरी में भैंस लेकर अपने घर लौट रहे एक 24 वर्षीय युवक एजाज डार की एक भीड़ ने पीट–पीट कर जान ले ली।

इनमें से अधिकतर घटनाओं में हमलावर शायद ही पीड़ितों को जानते होंगे। उनके लिए इन निर्दोष लोगों पर अत्याचार के लिए केवल उनकी मुस्लिम पहचान ही काफी है। पीड़ितों को सुरक्षा देने और उनके लिए न्याय को सुनिश्चित करने के बजाय, यूपी सरकार इन घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और आवाज उठाने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही निशाना बना रही है। पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि पीड़ितों और सेक्युलर ताकतों के बीच से इस रुझान के खिलाफ सामाजिक, कानूनी व राजनीतिक हर मोर्चे पर संयुक्त कोशिशें होनी चाहिएं।

मुस्लिम उपदशकों की गिरफ्तारी यूपी चुनाव से पहले बदनाम करने के अभियान का हिस्सा

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निर्दोष मुस्लिम उपदेशकों की गिरफ्तारी आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा शुरू किए गए बदनाम करने के अभियान का हिस्सा है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी एटीएस के द्वारा जबरन धर्मांतरण के आरोप में डॉक्टर मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काज़ो जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी की निंदा करता है। यूपी एटीएस अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की प्राइवेट सेना की तरह काम कर रही है। जबरन धर्मांतरण का विचार ही अपने आप में बेतुका है। यूपी सरकार ने वास्तव में संविधान द्वारा दिए गए धर्म परिवर्तन के अधिकार को दागदार किया है और इसे आतंकवादी गतिविधियों की श्रेणी में डाल दिया है। राज्य में लागू दमनकारी धर्मांतरण विरोधी कानून पूर्ण रूप से भारतीय संविधान की धारा 25 के तहत दी गई विवेक की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसके प्रचार की विचारधारा के खिलाफ है।

योगी सरकार जानती है कि हर मोर्चे पर उसकी नाकामी और कुशासन के कारण जनता के बीच एक असंतोष है। इसलिए वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भय पैदा करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नए तरीकों की तलाश

में है। वे मीडिया के एक वर्ग का इस्तेमाल करके रोहिंग्या शरणार्थियों, मुस्लिम आबादी और जबरन धर्मांतरण के बारे में फर्जा खबरें फैला रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले 'लव जिहाद' के पापगंडे का इस्तेमाल किया। यूपी पुलिस काले कानूनों के तहत फर्जा मुकदमों में निर्दोष मुसलमानों को गिरफ्तार करती रही है। जिसके बाद उन निर्दोषों की दुर्दशा के बारे में न कोई पूछता है और न उसका कोई ख्याल करता है। फिर सालों तक कैद रहने के बाद अदालतों से उन्हें बरी कर दिया जाता है।

पॉपुलर फ्रंट राज्य और देश भर को लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करता है कि व निर्दोषों पर अत्याचार को कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से रोके।

अनीस अहमद
महासचिव,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली